गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों में मूलभूत सेवाओं के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय आयोग

2670.**श्री शिव चरण सिंह:**
श्री गोविंदराम मिरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत न्यूनतम सेवाओं में हुई कमी का अध्यय करने के लिए कोई उच्च स्तरीय आयोग गाठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये है;

(ग) यहि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्यों के विकास के लिए आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के संबंध में बैकलॉग तथा मूलभूत ढांचे के क्षेत्रों में गैप की गहराई से जांच करने हेतु सरकर ने एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया था।

(ख) आयोग ने 7 मार्च, 1997 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) और (घ) अन्य बातों के साथ-साथ ये सिफारिशें कृषि क्षेत्र, बागवानी तथा प्लांटेशन, मत्स्यपालन एवं पशुपालन, सिंचाई, बाढ़ – नियंत्रण, वन पर्यावरण, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, नागारिक उड्ड्यन, अन्तर्देशीय जल परिवहन नीति, दूरंसंचार, प्रसारण, हाइड्रोकार्बन सेक्टर, कोयला एवं विद्युत , उद्योग, हथकरघा तथा हस्तशिल्प, शहरीकरण एवं विश्ष योजना, व्यापार एवं ट्रांजिट, पर्यटन, बैंकिंग एवं वित्त आदि क्षेत्रों में आधारभूत न्यूनतम सेवाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित है। एक प्रभावी प्रबोधन संगठन तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता की सिफारिश भी की गई है। सिफारिशों को उचित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रोसेस किया जाएगा।

दिल्ली में हत्याएं

2671. **श्री राम देव भंडारी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या यह सच है कि दिल्ली में हर सोलह घंटो में एक हत्या और एक बलात्कार की घटना घट रही है;

यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

यदि नहीं,तो दिल्ली में हत्या और बलात्कार का मासिक औसत क्या है; और

इस मामले में क्या कार्यवही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) 1996 के दौरान दिल्ली में सूचित किए गए हत्या एवं बलात्कार के मामलों की संख्या क्रमश: 518 और 484 थी। हत्या के मामले में मासिक औसत 43 तथा बलात्कार के मामले 40 बनती है।

(घ) हत्या एवं अपराध सहित, अपराध की रोकथाम करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाये गये कदमों में, अन्य के साथ –साथ शामिल है:-

(1) गश्त की मौजूदा बीट प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया गया है। ज्ञात बदमाशों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कोई पुरानी आपराधिक पृष्ठिभूमि न होने के कारण पुलिस के जाल से प्राय: बच निकलने वाले अपराधियों पर कडी नजर रखने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है।

(11) खतरनाक अपराधियों के आवागमन के बारे में आसूचना लगातार तैयार की जाती है और इन अपराधियों की धर-पकड़ के लिए छापे मारे जाते है। खासतौर से अंधेरी रातों में गश्त बढ़ा दी गई है क्योंकि आपराधिक गिरोहों में ऐसी रातों में ही सक्रिय होने की प्रवृत्ति होती है।

(111) जेल से रिहा हुए अपराधियों की गातिविधियों तथा उनके द्वारा जीविकोपार्जन के लिए अपनाए जाने वाले साधनों का सत्यापन किया जाता है और उन पर निगरानी रखी जाती है।

(1V) अपने नौकरों का सत्यापन कराने के लिए नागारिकों को सक्रिय करने के लिए नौकरों का पूर्ववृत सत्यापन अभियान चलाया गया।

(v) राजधानी की विभिन्न कालोनियों में "पड़ोसी निगरानी योजना" शुरू की गई है। बीट अधिकारी समय-समय पर वृद्व नागरिकों के पास जाते रहते है।

(VI) जघन्य अपराधों का पता लगाने के लिए अन्वेषण के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है।

(VII) गंभीर अपराधों की जां-पड़ताल प्रभावी तरीके से करने के लिए दिल्ली पुलिस के अधीन एक विशेष कार्य बल बनाया गया है।

Deteriorating situation of Law and Order in the states

2672. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news appearing in the newspapers on 3.2.1997 wherein it has been stated that the police in some of the States including Bihar is not capable of meeting/facing the rioteous, law and order situation and violence conditions and are dependent on central forces etc;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government in making the State police alert and competent to face the riots, violence and law and order in the respective States to protect the lives and properties of the people living therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (c) According to the news item published in the Times of India in its issue dated 3.2.1997, the Home Minister had, inter alia, emphasised that sending Central para-military forces to trouble spots alone could not solve the problem.

As 'Public Order' and 'Police' are State subjects, it is primarily for the State Governments concerned to take necessary action to deal with riots, violence and other law and order situations in their respective jurisdiction and to protect the lives and properties of the people. The Central Government, on its part, apart from sending advisories, has been providing financial assistance to the State Governments for improving their policing infrastructure.

Bill on protection of Scheduled Tribes in Kerala

2673. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Kerala Scheduled Tribes (Restriction on Transfer of Lands and Restoration of Alienated Lands) Amendment Bill, 1996 is against the Constitutional provision which enjoined on the State Government to protect the Scheduled Tribes from all sorts of exploitation and promote their socio-economic conditions; and

(b) the reasons for not returning the Bill to the State Legislature early?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFARS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) The Kerala Scheduled Tribes (Restriction on Transfer of Lands and Restoration of Alienated Lands) Amendment Bill, 1996, as passed by the State Legislature and reserved by the Governor of Kerala, has been received by the Union Government for the assent of the President. The Bill is receiving the attention of the Government.

अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे तीर्थ यात्रियों की मौत

2674. **श्री राघवजी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

पिछले वर्ष अमरनाथ की यात्रा में मरने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या क्या है;

कितने तीर्थ यात्रियों के परिवारों को मुआवजे की राशि दे दी गयी है; और

(ग) मृत यात्रियों के बाकी बचे परिवारों को अब तक मुआवजे की राशि प्रदान नहीं करने के क्या कारण है और इसका भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) अमरनाथ यात्रा त्रासदी, 1996